मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

अस्पताल बने लूट के अड्डे 3
पेरिस में मोदी डील 4
संघ के शिकार राहुल ? 5
47 वर्ष में बिल्डिंग जर्जर 8

वर्ष 31 अंक -40 फ़रीदाबाद 30 सितम्बर -6 अक्टूबर 2018 फोन : - 9999595632 ₹ 2.50

'आयुष्मान': इलाज भले ही न मिले, ढोल तो यूं ही बाजेगा

फ़रीदाबाद (म.मो.) इसी वर्ष फ़रवरी-मार्च के बजट सत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश भर के सबसे ग़रीब 50 करोड़ लोग़ों को 5 लाख तक का इलाज मुफ़्त देने की घोषणा करके आगामी लोकसभा चुनाव के लिये अपना वोट बैंक तैयार करने का प्रयास शुरू किया था। बीते करीब 6 माह की तैयारी के बाद 23 सितम्बर को दुनिया की सबसे बड़ी 'स्वास्थ्य सेवा' का शुभारंभ किया गया। भाजपा सरकार बखूबी समझती है कि जमीनी स्तर पर बिल्कुल खोखली इस योजना के द्वारा जनसाधारण को भ्रमित करने के लिये प्रचारतंत्र का अत्याधिक सहारा लेना बहुत ही जरूरी है। इसलिये देश भर के ज़िले-ज़िले में मंत्री स्तरीय समारोह करके इस नकली स्कीम को लांच किया गया।

पाखंड की इसी श्रृंखला में स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर ने रविवार दिनांक 23 सितम्बर को ज़िले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल बादशाह खान में इसे पूरे ताम-झाम के साथ लांच किया। इस अवसर पर सीएमओ व डिप्टी सीएमओ के अलावा कुछ अन्य सरकारी डॉक्टर व प्रशासनिक अधिकारी तो मौजूद थे लेकिन जनता के नाम पर सरकारी आंगनबाड़ी वर्कर तथा आशा वर्कर ही मौजूद थीं। कुछ वे लोग भी थे जो अस्पताल की सस्ती कैंटीन में खाना खाने आये थे लेकिन खाने की जगह उन्हें गूजर के भाषण से ही पेट भर कर जाना पड़ा। वास्तव में यह समारोह उस कैंटीन में ही किया गया था जहां ग़रीब लोग आकर सस्ता खाना खाते हैं। गूजर अलाप से पूर्व उपस्थित लोग़ों को प्रधानमंत्री मोदी का वह भाषण भी सीधे सुनाया व दिखाया गया जो वे उस वक्त छत्तीसगढ़ में दे रहे थे।

पाखंड की लांचिंग करने के लिये वे गोल्डन कार्ड भी दिखाये गये जिनके द्वारा तमाम सूचिबद्ध अस्पतालों में उनका मुफ़्त इलाज हो पायेगा। समझने वाली बात यह है कि इस पूरी ड्रामेबाज़ी में 5 तथाकथित लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड प्रस्तुत किये गये न कि उनको दिये गये। ये कार्ड किसी को दिये भी नहीं जायेंगे। इस तरह के कार्ड तो उन मरीज़ों के लिये उसी वक्त अस्पताल में प्रिंट करके दिये जायेंगे जब वे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भेजी गयी चिट्ठी लेकर अस्पताल आयेंगे। है न मजेदार बात। मुंगेरी लाल के हसीन सपनो जैसी इस योजना के अनुसार ज़िले के 1.33 लाख परिवारों यानी करीब आठ लाख लोग़ों के नाम के पत्र मोदी जी घर-घर भेजेंगे। देश भर में इस तरह के करीब 50 करोड़ पत्र भेजे जायेंगे। डाक व्यवस्था का तो बेड़ा गर्क हुआ ही पड़ा है, फ़िर यह चिट्ठी कौन पहुंचायेगा? इसके लिये गूजर ने आशा वर्करों की ड्यूटी लगाने की घोषणा की तो उन्होंने बेझिझक भरी सभा में ही इस बेग़ार से साफ़ इंकार कर दिया।

प्रधानमंत्री मोदी की चिट्ठी जैसी पहुंचेगी उसके आसार तो अभी से दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की चिट्ठियां कौन से 1.33 लाख परिवारों को पहुंचेगी, उसकी बानगी भी मिल चुकी है। इस सूची में एनआईटी के पूर्व विधायक एवं मंत्री एसी चौधरी व उनके परिजनों के नाम तो सामने आ ही चुके हैं और कितने ऐसे 'ग़रीब जरूरतमंद' इसमें

मोदी का 'आयुष्मान भवः'

शामिल हैं, यह भी समय-समय पर पता चलता रहेगा। सरकार की कार्यक्षमता का पता इसी बात से चलता है कि बीते 6-7 माह में इनसे जरूरतमंद लाभार्थियों की सही सूची तक नहीं बन पाई। जानकारों के मुताबिक सन् 2011 में हुई मतगणना के आधार पर देश भर में ये सूचियां बनाई गयी हैं। यानी कि देश भर की सूचियों में इसी तरह का तमाशा मिलना स्वाभाविक है।

कोई भी बड़ा निजी अस्पताल शामिल नहीं

सरकार के इस फ़र्जीवाड़े में तमाम बीमा कम्पनियों व बड़े निजी अस्पतालों द्वारा इन्कार कर दिये जाने के बाद 19 सितम्बर को हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव जोवल ने वीडियो कांफ्रेंस में तमाम ज़िलों के उपायुक्तों को कहा कि वे तमाम बड़े निजी अस्पतालों को बुलायें, उन्हें प्यार से समझायें फ़िर भी न समझें तो उन्हें सरकार के नख-दंत के रूप में अस्पताल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट व अन्य सरकारी ताकतों से अवगत करायें। लेकिन इसके बावजूद भी कोई बड़ा अस्पताल इसमें शामिल नहीं हुआ।

छोटे निजी अस्पतालों में से केवल वे शामिल हुए हैं जिनके पास काम नहीं है अथवा खानापूर्ति के लिये नाम लिखवा दिया गया; आयुष्मान का मरीज़ जब कोई आयेगा तब की तब देखी जायेगी। हां 3 सरकारी अस्पताल-बीके बल्लबगढ़ वाला तथा सेक्टर 8 का ईएसआई अस्पताल जरूर पक्के तौर पर शामिल हैं।

संदर्भवश सुधी पाठक यह अवश्य समझ लें कि ईएसआईसी का केवल सेक्टर 8 वाला अस्पताल ही इसमें शामिल है न कि एनएच-3 वाला मेडिकल कॉलेज अस्पताल जिसे सीधे तौर पर ईएसआई कार्पोरेशन चलाती है;जबकि सेक्टर 8 वाले का पूरा नियंत्रण हरियाणा सरकार के हाथों में है। करीब 40 वर्ष पुराने इस अस्पताल की तारीफ़ यह है कि इसकी 200 बेड की इमारत में केवल 50 बेड का ही अस्पताल चलाने का ड्रामा किया जा रहा है। ड्रामा इसलिये कि यहां कभी भी 10-15 मरीज़ से अधिक दाखिल नहीं रहते। कारण यह कि न तो यहां ऑपरेशन थियेटर चलता, न यहां डॉक्टर व अन्य स्टाफ़ आवश्यकता के अनुरूप मौजूद रहता है। यहां से तो केवल मरीज़ों को पहले निजी अस्पतालों को और अब एनएच 3 को रैफ़र किया जाता है।

यदि खट्टर सरकार की नीयत सही होती और कुछ काम करने की इच्छा होती तो बीते 4 वर्षों में इसी अस्पताल को 200 बेड का बना कर सही ढंग से चलाया जा सकता था। मज़े की बात तो यह है कि इस काम के लिये पैसे की कोई कमी नहीं है क्योंकि यहां खर्च होने वाले हर 8 रुपये में से केवल एक रुपया हरियाणा सरकार व शेष 7 रुपये ईएसआईसी खर्च करती है। दूसरे शब्दों में यदि राज्य सरकार इस पर 80 करोड़ खर्च करे तो 70 करोड़ ईएसआईसी देती। लेकिन यहां तो झगड़ा नीयत का है, काम कौन करे? केवल ड्रामेबाज़ी से ही काम चलाना चाहते हैं ये नेता लोग।

आयुष्मान में एक और पंगा यह है कि जो मरीज़ मोदी की चिट्ठी लेकर अस्पताल में आयेगा, उसका गोल्डन कार्ड का प्रिंट निकालने के लिये कम्प्यूटर, बायोमीट्रिक (अंगूठा लगाने वाली मशीन) तथा प्रिंटर भी अस्पताल को अपने पल्ले से लगाना पड़ेगा। यह सारा सौदा एक लाख से कम का नहीं पड़ता। इसके अलावा इन मशीनों पर काम करने के लिये दो कर्मचारी (आयुष्मान मित्र) भी अस्पताल अपने खर्चे पर रखेंगे। देश भर में सैंकड़ों करोड़ का तो यह सामान ही आ जायेगा और 2-2 कर्मचारियों का वेतन अलग से। इसके बाद बिजली संकट व सर्वर डाउन रहने की समस्या तो यहां स्थाई रूप से मौजूद है ही। इस सबके बदले में प्रति मरीज़ जो खर्चा सरकार देने का वायदा कर रही है वह बहुत ही अपर्याप्त है।

कृष्णपाल का इतना बुझा हुआ चेहरा कभी नहीं दिखा

केन्द्रीय मंत्री गूजर का इस कदर बुझा हुआ चेहरा किसी ने उनके चुनाव हारने पर भी कभी नहीं देखा था जितना बुझा एवं मुरझाया हुआ इस लांचिंग के वक्त दिखाई दे रहा था।

शेष पेज दो पर

शिव टूल्ज़ इन्जीनीयरिंग की दादागीरी के सामने पुलिस व श्रम विभाग तो लाचार हैं ही, श्रम मंत्री भी फेल

खाई हुई रिश्वत का हक भी अदा किया पुलिस ने

फ़रीदाबाद (म.मो.) डबुआ-नवादा रोड पर स्थित उक्त कम्पनी के तीनों प्लांटों में कुल मिलाकर 400 से 600 तक महिला व पुरूष मज़दूरी करते हैं। किसी को भी न तो कोई नियुक्ति पत्र दिया जाता है न वेतन स्लिप। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के नाम पर सभी को हेल्पर श्रेणी में रखा जाता है। इसके बावजूद कम्पनी में दक्ष मज़दूरों द्वारा चलाई जाने वाली तमाम मशीनें दिन-रात धड़ाधड़ चलती हैं। मतलब साफ़ है कि दक्ष व अति दक्ष मज़दूरों को भी, न्यूनतम वेतन के मामले में हैल्पर ही दिखाया जाता है। इसके चलते वहां आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं में मज़दूरों के अंग भंग होते रहते हैं।

अंग-भंग होने की स्थिति में प्रबंधक उसे प्राइवेट अस्पताल से छोटा-मोटा इलाज करा कर भगा देते हैं। कानूनी तौर पर यहां ईएसआई लागू होनी चाहिये जिससे सभी श्रमिकों को उचित चिकित्सा सेवा के अतिरिक्त दुर्घटना होने पर पूरा मुआवज़ा व पेंशन इत्यादि मिल सके। लेकिन तथाकथित भ्रष्टाचार मुक्त इस देश में यह भ्रष्टाचार का ही कमाल है कि इतनी बड़ी फ़ैक्ट्री में इएसआई लागू नहीं है। और तो और इससे भी बड़ा गबन-घोटाला कम्पनी पीएफ़ (भविष्य निधि) के नाम पर कर रही है। इसके नाम पर मज़दूरों के वेतन से पैसा तो काटा जा रहा है लेकिन पीएफ़ में जमा कराने की बजाय मालिकान खुद ही इस फ़ंड को डकार जाते हैं। भारतीय दंड

संहिता की धारा 406 व 420 के तहत यह एक दंडनीय अपराध है लकिन लगातार हो रहे इस अपराध के बावजूद इस महान देश में कोई देशभक्त इन अपराधियों को पूछने वाला नहीं।

पुलिस के सक्रिय सहयोग से मालिकान के गुंडों की दहशत इतनी है कि यूनियन बनाना तो दूर कोई मज़दूर सिर उठा कर उनसे बात तक नही कर सकता। इसके बावजूद यहां काम करने वाली माया ने इन लुटेरे मालिकान के खिलाफ़ आवाज़ बुलंद कर दी। माया ने यहां 9 फ़रवरी 2013 को काम शुरू किया था। काट-पीट कर वेतन मिलता था मात्र 6000/-। जबरन ओवर टाइम तो कराया जाता था। लेकिन उसका भुगतान आधा-अधूरा ही किया जाता था। हैल्पर और वह भी महिला होते हुये दिनांक 3 अगस्त 2016 को उन्हें पावर प्रेस पर जबरन काम पर लगाया गया जबकि वह मशीन उस दिन कुछ ठीक नहीं चल रही थी । वैसे भी सामान्य तौर पर इस तरह की भारी मशीनों पर महिलाओं को नहीं लगाया जाता। जाहिर है जब काम भारी और दक्षतापूर्ण हो तो महिला हैल्पर की दुर्घटना होना स्वाभाविक ही थी, सो हो गयी। माया का बायां हाथ प्रेस में आ गया। हाथ की हथेली सहित चार अंगलियां कट गयी, केवल एक अंगूठा किसी तरह बच पाया। ईएसआई कवर न होने के चलते उसे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना पड़ा। एक हाथ से विकलांग माया को इसका न तो कोई मुआवज़ा मिला और न ही विकलांगता पेंशन। नौकरी के और लाले पड़ गये क्योंकि किसी विकलांग को कोई भी कम्पनी अपने यहां रखकर राज़ी नहीं।

अपनी इस दुर्घटना की शिकायत माया ने तुरंत स्थानीय डबुआ पुलिस चौकी में की थी, परन्तु वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। हो भी कैसे सकती थी जब चौकी चलाने का खर्चा कम्पनी देती हो तो पुलिस मज़दूरों का पक्ष भला कैसे ले सकती है। चौकी में लगा वाटर कूलर तक इस बात की गवाही दे रहा

शेष पेज दो पर